

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2017 निगरानी

1. रामनारायण पुत्र हरबक्श
2. रामसहाय पुत्र सेवा
3. श्योराम पुत्र रूपा
4. भगवान सहाय पुत्र गोविन्दा
5. रंगलाल पुत्र घासीलाल

समस्त जाति मीना निवासी पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. नरसी पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत पालुन्दा पं०स० लालसोट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पालुन्दा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकर्तागण



निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 रा० पं० रा० अधिनियम विरुद्ध प्रस्ताव सं० 5 ग्राम पंचायत पालुन्दा पं०स० लालसोट जिसके अनुसार विपक्षी सं० 1 के नाम दिनांक 22.09.2017 को प्रश्नगत पट्टा सं० 38 प्रचलित फरमाया गया है।

उपस्थिति : श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता निगरानीकर्तागण।

: श्री एच०एन० माठा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता 1 लगा० 2 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 11.09.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पक्षकारगण प्रकरण ग्राम पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा के निवासीयान है। पक्षकारान एवं अन्य सहभागीदारान के कृषि भूमियों के बीच आराजी खसरा नं० 50 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी की भूमि स्थित है। जिसमे पक्षकारगण एवं अन्य सहखातेदारान के रिहायशी मकानात आम पशुबाडा एवं कुछ पक्के मकान बने हुये हैं। यह भूमि पक्षकारगण एवं अन्य सहखातेदारी की आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत पालुन्दा द्वारा पूर्व में निगरानीकर्तागण के पूर्वजो के नाम पट्टे दिये जा चुके हैं। उक्त आबादी भूमि में जिस पर निगरानीकर्तागण का कब्जा है का पट्टा विपक्षी सं० 2 सरपंच ग्राम पंचायत पालुन्दा द्वारा प्रस्ताव सं० 5 द्वारा विपक्षीगण सं० 1 के नाम पूर्व पश्चिम 70 फीट लम्बाई एवं उत्तर दक्षिण 38 फीट चौड़ाई के माप का पट्टा सं. 38 दिनांक 22.09.2017 को प्रचलित फरमा दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा सं. 38 दिनांक 22.09.2017 के विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई है।



जिला कलेक्टर  
दौसा

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई तथा ग्राम पंचायत पालुन्दा का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टे को देखते ही ज्ञात होता है कि इसमें कोई प्रविष्टिया नहीं की गई है। वर्ष 1974 से निगरानीकर्तागण का कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारियों का कब्जा किस आधार पर मान लिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत आबादी भूमि जिसमें चार हिस्से हैं तथा निगरानीकार अपने-अपने हक एवं हिस्से पर आबाद है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकारान की पट्टेशुदा भूमि को निरस्त किये बिना किसी अन्य को पट्टा किस प्रकार से दे सकती है। इस प्रकार गैरनिगरानीकार सं. 01 को जारी पट्टे विधि विरुद्ध होने के कारण से निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकारान द्वारा निवेदन किया गया की गैरनिगरानीकार सं. 01 को जारी प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए दिया गया हैं। पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पंचायत में दिया गया तथा जिस पर नियमानुसार पट्टा फीस की रसीद काटी गई है। तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी गठित की गई हैं एव विधिवत् आपत्ति नोटिस जारी किया गया था। गवाहान के आबादी भूमि के कब्जे सम्बन्धित बयान लिये गये एवं ग्राम पंचायत की मितिग में पट्टा देने का निर्णय कर विधिवत् पट्टा जारी किया गया है। जिस आबादी भूमि पर अप्रार्थी का वर्षों पुराना कब्जा है तथा अप्रार्थी के कच्चे-पक्के घर बने हुए है। इसी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने जो पट्टे पेश किये है। वह पट्टे की फोटो स्टेट कॉपी है। जो कानूनन पढने योग्य नहीं है। दूसरी बात पट्टे उस जगह के नहीं है जहां अप्रार्थी के पट्टे बनाये गये है। निगरानीकर्ता पिछले 40 वर्षों से ग्राम पालुन्दा में निवास नहीं कर रहे है। वे कुन्तलवास में पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे बनाते समय आपत्ति नोटिस जारी किया था। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। जबकी अगर कोई पट्टे निगरानीकार के पास हो तो आपत्ति पेश करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई। निगरानीकर्ताओं ने जो पट्टे पेश किये है वह सभी निःशुल्क पट्टे है। निःशुल्क पट्टे के बारे में प्रावधान है की पट्टा भूमि पर एक वर्ष में निर्माण होना चाहिए अन्यथा निःशुल्क पट्टा निरस्त समझा जायेगा। निगरानीकर्ताओं ने रजिशवश निगरानी पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

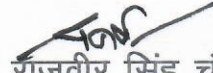
हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पट्टा भूमि एवं ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 को जारी पट्टा से सम्बन्धित पट्टा भूमि में समानता नहीं दिखाई देती है। ग्राम पंचायत पालुन्दा से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 को प्रश्नगत पट्टा सं. 38 दिनांक 06.10.2017 विधिवत् जारी किया गया हैं। हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा पट्टा सं. 38 दिनांक 22.09.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना व्यक्त किया गया है।



प्रकरण संख्या 26 / 2017 निगरानी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं. 38 दिनांक 22.09.2017 ग्राम पालून्दा के विरुद्ध निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



  
( राजवीर सिंह चौधरी )

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( राजवीर सिंह चौधरी )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा